

# दि कर्मक पोस्ट

Global  
School Of  
Excellence,  
Obedulaganj

वर्ष : 10, अंक : 15

( प्रति बुधवार ), इन्दौर, 27 नवंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

## शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में अज्ञात यौगिक की पहचान की

नई दिल्ली। शोधकर्ताओं ने अब पानी में क्लोरोनाइट्रामाइड आयन की पहचान की है, जिसे रासायनिक रूप से सीएलएनएनओ 2 के रूप में लिखा जाता है, जो अकार्बनिक क्लोरैमाइन के टूटने के बाद बचा अंतिम उत्पाद है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्लोरैमाइन मिले पीने के पानी में पहले से अज्ञात यौगिक की खोज करने की जानकारी दी है। अकार्बनिक क्लोरैमाइन का उपयोग आम तौर पर हैजा और टाइफाइड बुखार जैसी बीमारियों से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पीने के पानी को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है।

शोधकर्ताओं ने अब पानी में क्लोरोनाइट्रामाइड आयन की पहचान की है, जिसे रासायनिक रूप से सीएलएनएनओ 2 के रूप में लिखा जाता है, जो अकार्बनिक क्लोरैमाइन के टूटने के बाद बचा अंतिम उत्पाद है। हालांकि इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अन्य विषैले यौगिकों के साथ इसकी अधिकता और समानता चिंताजनक है। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का आकलन करने के लिए आगे अध्ययन किए जाने चाहिए। खैर इस यौगिक की पहचान करना ही एक चुनौती के साथ सफलता रही है। यह शोध साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का आकलन करने के लिए आगे अध्ययन किए जाने चाहिए। शोधकर्ता ने शोध में बताया कि वैज्ञानिकों को दशकों से यौगिक के बारे में पता है, लेकिन वे इसे पहचानने में असमर्थ हैं। उन्होंने खुद 10



साल पहले रहस्य को सुलझाने की कोशिश शुरू की थी। शोधकर्ता के मुताबिक, यह कम आणविक भार वाला एक बहुत ही स्थिर केमिकल है। यह एक ऐसा रसायन है जिसे खोजना बहुत मुश्किल है। सबसे कठिन काम था इसकी पहचान करना और यह साबित करना कि यह वही संरचना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें प्रयोगशाला में यौगिक को संश्लेषित करने में सक्षम होना शामिल था, जो पहले कभी नहीं किया गया था। फिर नमूनों को विश्लेषण के लिए भेजा गया इस नए यौगिक के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में कई प्रश्न होंगे, जिनका पहले किसी भी विषाक्तता अध्ययन में मूल्यांकन नहीं किया जा सका था। पीने के पानी के कीटाणुनाशकों के केमिकल का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता ने शोध में बताया, यह अच्छी तरह से पहचाना हुआ है, जब हम पीने के पानी को कीटाणुरहित करते हैं, तो कुछ विषाक्तता पैदा होती है, जो लंबे समय में और बढ़ सकती है। कुछ लोगों को कई दशकों तक पीने के पानी से कैंसर हो सकता है। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का आकलन करने के लिए आगे अध्ययन किए जाने चाहिए। इस यौगिक की पहचान करना उस प्रक्रिया में एक अहम कदम है। क्या क्लोरोनाइट्रामाइड आयन किसी कैंसर से जुड़ा होगा या इससे अन्य प्रतिकूल स्वास्थ्य जोखिम होंगे, इसका मूल्यांकन भविष्य में शिक्षाविदों और नियामक एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में किया जाएगा। कम से कम, इस खोज की बदौलत अब इस यौगिक पर विषाक्तता संबंधी अध्ययन पूरा किया जा सकता है। शोधकर्ता ने बताया भले ही विषाक्त न हो, इसकी खोज से यह समझने में मदद मिल सकती है कि विषाक्त पदार्थों सहित अन्य यौगिक कैसे बनते हैं। अगर हम जानते हैं कि कोई चीज कैसे बनती है, तो हम संभावित रूप से इसे नियंत्रित कर सकते हैं।

## बढ़ते प्रदूषण से दुर्गापुर में सबसे खराब हैं हालात, गिरावट के बावजूद दिल्ली में बेहद खराब है हवा

मुंबई। प्रदूषण के मामले में आज फिर दुर्गापुर अक्वल रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पास पहुंच गया है। बता दें कि कल दुर्गापुर में एक्वआई 360 दर्ज किया गया था। वहीं बैरकपुर (366) दूसरे जबकि हावड़ा (350) तीसरे स्थान पर है।

इसके बाद दिल्ली चौथे स्थान पर है, जहां कल से प्रदूषण में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक %बेहद खराब% बना हुआ है। बता दें कि कल प्रदूषण के मामले में दिल्ली देश में दूसरे स्थान पर थी। कल के मुकाबले में देखें तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में छह अंकों का सुधार जरूर आया है। हालांकि वहां हवा में घुला जहर लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है। दिल्ली की तरह ही देश में आसनसोल (328), हाजीपुर (325), हल्दिया (322), बहादुरगढ़ (315), तालचर (306), भागलपुर (304) और अररिया (303) में प्रदूषण से स्थिति %बेहद खराब% है। इन सभी शहरों में सूचकांक 300 के पार है। हालांकि राहत की बात यह रही कि देश में कल से %बेहद खराब% हवा वाले शहरों की गिनती में करीब 27 फीसदी की गिरावट आई है। दिल्ली की तरह ही पड़ोसी शहर फरीदाबाद में भी कल से वायु

गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है, जहां 30 अंकों की गिरावट के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरकर 215 पर पहुंच गया। हालांकि फरीदाबाद में अभी भी वायु गुणवत्ता %खराब% बनी हुई है। फरीदाबाद की तरह ही देश के छोटे बड़े 50 अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता %खराब% है। इन शहरों में अगरतला, अमृतसर, अंगुल, बागपत, बालासोर, बल्लभगढ़, भिवानी, भुवनेश्वर, बिहार शरीफ, बुलन्दशहर, बक्सर, चंडीगढ़, छपरा, कटक, दमोह, धनबाद, धुले, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गुम्मिडिपूडी, गुरूग्राम, ग्वालियर, हनुमानगढ़, हापुड, खुर्जा, किशनगंज, कोलकाता, लखनऊ, मालेगांव, मेरठ, मुरादाबाद, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, नागौर, नोएडा, पानीपत, परभनी, पटना, पिंपरी-चिंचवाड, राजगीर, सहरसा, समस्तीपुर, सिंगरौली, सिरसा, सोनीपत, टोंक, विशाखापत्तनम शामिल हैं। अच्छी खबर यह है कि देश में खराब हवा वाले शहरों की संख्या में कल से 31 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ देश में मदिकेरी की हवा सबसे साफ है, जहां एक्वआई 31 दर्ज किया गया है।



# जहरीली होतीं जीवनधाराएं



शिमला। गोमती में पहाड़ों से पानी नहीं आता है। हिमालय में बर्फ पिघलने से बनी नदियों के विपरीत गोमती हिमालय की तलहटी में ही पीलीभीत के माधोटांडा में फुलहर ताल से निकलती है। यह लगभग 960 किमी का सफर तय करती है और उत्तर प्रदेश के पंद्रह जिलों में बहती है। अपनी यात्रा में यह नदी 40 से अधिक छोटी-बड़ी सहायक नदियों से जल लेती है और आखिर में वाराणसी से 27 किमी की दूरी पर स्थित सैदपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है। गोमती के सर्पिले व घुमावदार अंदाज में बहने के कारण अंग्रेज इसे घूमती नदी कह देते थे। गोमती नदी ने कई तालाबों-झीलों और वेटलैंड्स को जन्म दिया, जिसका वजूद आज भी कायम है। बहरहाल आज यह एक भूली-बिसरी नदी है। पीलीभीत से निकलकर गोमती नदी जब लखनऊ में प्रवेश करती है तो वहां उसे नालों के पानी, रिवरफ्रंट और 25 से अधिक पुलों और अवरोधों का सामना करना पड़ता है।

यही कारण है कि गोमती का सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। यह नदी शहर को दो भागों में बांट देती है- सिस-गोमती और ट्रांस-गोमती। ट्रांस गोमती शहर का वह हिस्सा है जो नदी के दूसरी ओर है और अधिक विकसित व नियोजित है। गोमती नगर यहीं पर बसा है। सिस गोमती क्षेत्र में पुरानी कॉलोनियां हैं जिन्हें पुराना लखनऊ कहा जाता है। इसके अलावा लखनऊ में गोमती नदी की कई सहायक नदियां भी बहती हैं जिन्हें हम मात्र सीवेज ढोने वाले नालों के नामों से जानते हैं। सत्तर के दशक में गोमती

के अलावा लखनऊ में रैठ, बेहता, कुकरैल, बख, नगवा, अकरदी, झींगी, लोनी और सई नाम की नौ छोटी नदियां बहती थीं। इनमें से चार नदियां पिछले पचास वर्षों में गायब हो गई हैं क्योंकि उन पर घर, कॉलोनियां और सड़कें बना दी गई हैं और तीन नदियों को आज नालों के नाम से जाना जाता है। लखनऊ का विकास दरअसल गोमती और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट को खत्म करके किया गया। खादर इलाके में पॉश कॉलोनी बसायी गई और नदी को संकरा करके रिवरफ्रंट बना दिया गया। कोई 15 साल पहले मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे एक छोटा सा हिस्सा था जहां प्रकृति की खूबसूरती का सुखद एहसास था, लेकिन अफसोस आज वह स्थान भी गंदे नाले के नदी में गिरने से चला गया है और लखनऊ में गोमती नदी का एक सुन्दर और स्वच्छ किनारा या पसंदीदा जगह तलाशने से भी नहीं मिलता। शहरीकरण और अचल संपत्ति के विस्तार ने वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य और ऐसे दर्शनीय स्थलों को मार डाला है। आजकल कई अन्य शहरों में एक नदी को ढूँढना जो अछूता और सुंदर है, वास्तव में मुश्किल है। पिछले 50 वर्षों में हमने धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी जीवन-धाराओं को जहरीला बना दिया है। हमने प्रकृति के अमूल्य उपहारों की कद्र करना और उनकी रक्षा करना नहीं सीखा है। लखनऊ शहर में जलापूर्ति के लिए गोमती नदी प्रमुख सतही जल स्रोत है। गोमती नदी के पानी को उपचारित करने के लिए ऐशबाग (265 एमएलडी) और बालागंज (200 एमएलडी) में दो जल संयंत्र उपलब्ध हैं।

ब्रिटिश काल में वर्ष 1884 में नगर निगम बोर्ड के गठन के बाद वर्ष 1892 में स्टीम इंजन पंपों के द्वारा पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्था शुरू की गई। पहले यह व्यवस्था केवल 2 लाख की आबादी के लिए प्रस्तावित थी। जलापूर्ति का मुख्य स्रोत गोमती नदी ही थी और नदी के दाहिने किनारे गऊघाट पर कच्चे पानी को पंप करने के लिए पहला पंपिंग स्टेशन बनाया गया था और ऐशबाग में ट्रीटमेंट प्लांट (लखनऊ का सबसे पुराना ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित किया गया था। ऐशबाग वाटर वर्क्स में ट्रीटमेंट के बाद फिल्टर किया गया पानी कास्ट आयरन मेन नेटवर्क के माध्यम से वितरण के लिए शहर में पंप किया जाता रहा। इसके बाद 20वीं सदी के पहले हिस्से में पुराने स्टीम इंजन पंपों को बिजली से चलने वाली प्रणाली से बदल दिया गया। 1957 के आसपास जलापूर्ति व्यवस्था का एक बड़ा पुनर्गठन किया गया जहां पूरे शहर को छावनी सहित 11 जोनों में बांट दिया गया। 80 और 90 के दशक में शहर की नगरीय सीमा और आबादी के लिहाज से काफी वृद्धि हुई जिसका नतीजा जल कार्यों के कुप्रबंधन और शहर के विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति की भारी कमी के रूप में सामने आया। जलापूर्ति के उचित और न्यायसंगत वितरण के लिए वर्ष 1976 में लखनऊ शहर के लिए जलापूर्ति मास्टर प्लान में लखनऊ शहर को पांच जल जिलों (वाटर डिस्ट्रिक्ट) में विभाजित किया गया था। जिलों को आगे 32 जोनों में विभाजित किया गया। नगरीय विकास के साथ ही पीने के पानी की मांग बढ़ती चली गई। लखनऊ में दूसरा प्रमुख सतही स्रोत शारदा नदी से निकाली गई शारदा सहायक फीडर नहर है। कुछ साल पहले गोमती नगर के कठौता झील के एक हिस्से को शारदा सहायक फीडर नहर से भरा जाता है जिसे उपचारित करने के बाद इंदिरा नगर, विकास नगर और गोमती नगर के कई हिस्सों में जलापूर्ति (80 एमएलडी) की जाती है। वर्तमान में सतही जल स्रोतों से जल संयंत्रों की कुल जल क्षमता 545 एमएलडी है, जबकि इन संयंत्रों से वास्तविक जल उत्पादन 475 एमएलडी है। करता है जो गऊघाट के पास गोमती से मिलते हैं, यहीं पर पुराने लखनऊ को पीने का पानी गोमती नदी से पंप कर बालागंज पहुंचाया जाता है। सरकटा नाला और पाटा नाला का आधा अशोधित जल सीधे गोमती में मिल रहा है। सरकटा, पाटा और नगरिया नाले का शोधित जल पुनः सरकटा नाले में मिला दिया जाता है। इसकी वजह से गोमती में कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकटा नाले में पहले से ही गन्दा पानी गोमती में सीधे मिल रहा है। हालत ये है की पम्पिंग स्टेशन पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं और दौलतगंज एसटीपी केवल 60 से 65 एमएलडी सीवेज ही लेता है, बाकी 30 एमएलडी सीवेज सीधे गोमती में बहा दिया जा रहा है।

## जलवायु वित्त पोषण का सच, शहरी गरीबों तक पहुंच रहा है मात्र 3.5 फीसदी हिस्सा

मुंबई। एक नई रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि पिछले दो दशकों में वैश्विक जलवायु निधि का महज साढ़े तीन फीसदी हिस्सा शहरों में रह रहे गरीबों की मदद के लिए दिया गया है। यह निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित कमजोर समुदायों के लिए वित्त पोषण में एक बड़े अंतर को उजागर करता है। 'शहरी गरीबों के लिए जलवायु वित्त वैश्विक जलवायु समीक्षा' नामक यह रिपोर्ट को 18 नवंबर, 2024 को बाकू में संपन्न हुए कॉप29 सम्मेलन के दौरान सिटीज एलायंस द्वारा लॉन्च किया गया है। बता दें कि सिटीज एलायंस शहरों में रह रहे गरीबों और बेहतर शहरी विकास के मुद्दों पर काम करने वाला संगठन है। अपनी इस रिपोर्ट में 22 जलवायु निधियों और 3,428 परियोजनाओं से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इनमें से केवल 225 परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित थीं, जबकि महज 74 ने शहरी क्षेत्रों और कमजोर समुदायों दोनों को लक्षित किया था। इन परियोजनाओं को करीब 120 करोड़ डॉलर मिले, जो 2003 से 2023 के बीच वैश्विक जलवायु कोष द्वारा स्वीकृत 3,340 करोड़ डॉलर का महज साढ़े तीन फीसदी है। रिपोर्ट से पता चला है कि इसमें से आधे से ज्यादा करीब 53 फीसदी फंडिंग सब-सहारा अफ्रीका और पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को दी गई, जो करीब 62 करोड़ डॉलर है। इन क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। वहीं दक्षिण एशिया से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो उसे 120 करोड़ डॉलर में से महज चार फीसदी फंडिंग मिली, जोकि करीब पांच करोड़ डॉलर के बराबर है। इस क्षेत्र के लिए महज सात परियोजनाएं थी, जो कुल परियोजनाओं का दस फीसदी से भी कम है। यह वो क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश शहरी परियोजनाएं जलवायु अनुकूल पर केंद्रित थीं। यही वजह है कि इसमें से 51 फीसदी निधि इसी पर खर्च की गई। वहीं अनुकूलन निधि का करीब आधा हिस्सा पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों और संरक्षण के लिए था। वहीं करीब एक चौथाई पैसा पानी और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च किया गया, जबकि आपदाओं की रोकथाम और शहरों का जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कार्यक्रमों को थोड़ा कम हिस्सा मिला।



# 2023-24 में हाथियों के हमले से कुल 628 लोगों की मौत हुई



नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हंगामे के साथ हुई। आज विपक्ष के नेताओं ने संभल की घटना को लेकर संसद में हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं देश के अधिकतर हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण के चलते आज संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40 फीसदी तक कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम/घन मीटर) को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

यादव ने बताया कि सभी शहरों द्वारा अपने-अपने इलाकों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ये योजनाएं वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाना, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां और औद्योगिक प्रदूषण पर नजर रखती हैं। यादव ने कहा कि 18 शहरों ने

वित्त वर्ष 2023 से 24 में पीएम10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा किया है। संसद में एक और प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय कार्य समूह (एचएलडब्ल्यूजी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा छह राज्यों अर्थात् गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ, एस.ओ. 3060 (ई) दिनांक 31.07.2024 के अनुसार पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर मसौदा अधिसूचना को फिर से प्रकाशित किया गया है। केरल सरकार ने 02.11.2024 को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें स्थानीय स्वशासन विभाग से प्राप्त सुझावों के सत्यापन के आधार पर 12 जिलों के 29 तालुकाओं में फैले 98 गांवों में 8590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है। आज, संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में भारत द्वारा 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत की

गई तीसरी राष्ट्रीय संचार (टीएनसी) रिपोर्ट के आधार पर कहा, साल 2019 में कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन 420.97 मिलियन टन सीओ2 के समतुल्य था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, पिछले दो दशकों में कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन का हिस्सा जो 2000 में 23 फीसदी से 2010 में 18 फीसदी और 2019 में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 13.44 फीसदी था। सिंह ने कहा कि उत्पादित खाद्यान्न के प्रति टन उत्सर्जन में आम तौर पर कमी आई है, लेकिन हाल के वर्षों में उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण खाद्यान्न उत्पादन के प्रति हेक्टेयर उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। मानव-पशु संघर्ष को लेकर एक और प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में कहा कि इस साल हाथियों के हमले से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2023-24 में हाथियों के हमले से कुल 628 लोगों की मौत होने की जानकारी है। 2022-23 में यह संख्या 610 थी। सवाल के सिलसिले को जारी रखते हुए एक और सवाल के जवाब में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में साल 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान का हवाला देते हुए बाघों की आबादी में वृद्धि होने की बात कही, जिसकी अनुमानित संख्या 3682 (रेंज 3167-3925) है, जबकि 2018 में यह 2967 (रेंज 2603-3346) और 2014 में 2226 (रेंज 1945-2491) थी। सिंह ने बताया कि लगातार सैंपल किए गए क्षेत्रों की तुलना करने पर भारत में बाघों की आबादी छह फीसदी प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तटीय हिस्सों में कटाव को लेकर संसद में आज एक सवाल उठाया गया, जिसके जवाब में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के अध्ययन का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय तटरेखा का 33.6 फीसदी हिस्सा कटाव की स्थिति में है, 26.9 फीसदी हिस्सा बढ़ रहा है, और 39.6 फीसदी स्थिर अवस्था में है। सिंह ने कहा कर्नाटक में, कर्नाटक तट का लगभग 50 फीसदी हिस्सा स्थिर स्थिति में है, 26 और 24 फीसदी हिस्सा क्रमशः अभिवृद्धि और कटाव की स्थिति में है। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में अनुग्रह राशि को केंद्र प्रायोजित योजना एकीकृत वन्यजीव आवास विकास के तहत पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। सिंह ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच निधि साझा करने का अनुपात 60:40 है, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहां यह अनुपात 90:10 का है।

## 43वें आईआईटीएफ का मध्यप्रदेश मंडप बना प्रदेश के उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों और शिल्पकारों का मंच

भोपाल नई दिल्ली में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के मध्यप्रदेश मंडप में प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों और कला का विक्रय प्रदर्शन किया जा रहा है, जो प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और शिल्पकला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मंडप में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और जीआई उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए स्टाल लगाए गए हैं।

मध्यप्रदेश के मंडप में 25 से अधिक एमएसएमई उद्यमी, स्व-सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। मंडप में प्रदेश के विख्यात हैंडलूम और हस्तकला के विभिन्न स्टाल लगाए गए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित धार जिले के बाघ प्रिंट्स के शिल्पगुरु श्री मोहम्मद यूसुफ



खत्री का स्टाल सर्वाधिक लोकप्रिय हो रहा है। धार के रेवा स्व-सहायता समूह बाघ प्रिंट्स, उज्जैन के मुस्कान स्व-सहायता समूह बटिक प्रिंट्स, अशोकनगर के पाकीजा बुनकर अजरख प्रिंट्स के उत्पाद और सुरभि हैंडलूम चंदेरी साड़ी और सूट लेकर आए हैं। भारतीय बुनकर सहकारी समिति ने सीधी की प्रसिद्ध दरी, रग्स और रनर्स का स्टाल

लगाया है। इन दरियों की विशेषता बताई जा रही है कि वे 20 साल या अधिक तक चलेंगी। राजगढ़ की सनशाइन बुनकर सहकारी समिति बेडशीट, बेडकवर, सोफा कवर और पर्दों का विक्रय कर रही है। शिवपुरी के जैकेट्स, देवास के लैडर बैग्स, ग्वालियर के रेडीमेड वस्त्र और रीवा के एलोवेरा जैल भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। मंडप में राजगढ़ के अनन्या स्व-सहायता समूह और कटनी के ओमशांति स्व-सहायता समूह ने भी अपने स्टाल लगाए हैं। मंडप में गुना के वरुणदेव स्व-सहायता समूह के रिसाइकल्ड फूलों से निर्मित सुगंधित धूप और अगरबत्ती तथा देवास के दशमेश आयुर्हर्ब साँफटेक के कुकू, अष्टगंधा, उपले, धूपस्टिक और हवन सामग्री की भी मांग हो रही है।



# प्लास्टिक प्रदूषण से निजात के लिए अब बुसान में जुटे दुनिया भर के देश

बुसान। दुनिया भर के देशों में प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती से निपटने के समझौते पर सहमति बनाने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में नवंबर 2024 से बातचीत शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण केन्द्र (यूएनईपी) के नेतृत्व में हो रही इस वार्ता के जरिए एक कानूनी तौर पर बाध्य करने वाला दस्तावेज बनाने पर सहमति का प्रयास किया जाएगा।

पिछले दो साल से प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी उपाय ढूँढ़ने के लिए अन्तर-सरकारी (इंटर गवर्नमेंटल) स्तर पर वार्ता जारी हैं, जिसमें जमीन व समुद्र का भी ध्यान रखा गया। इसके बाद अब यह बैठक बुलाई गई है। बैठक से पूर्व संयुक्त राष्ट्र के सुप्रीमो एंतोनियो गुटेरेश ने एक वीडियो सन्देश के जरिए सभी देशों के प्रतिनिधियों से समझौते को आकार देने का आग्रह किया और कहा, हमारी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण में डूब रही है। हर साल हम लगभग 46 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, अधिकांश को जल्दी ही फेंक दिया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि साल 2050 तक महासागर में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से अधिक हो जाएगी। हमारे खून में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पहुंच गए हैं, जो हमारे शरीर के लिए कई तरह समस्याओं की वजह बन रहे हैं, जिनके बारे में हमने अभी समझना शुरू ही किया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक प्रेस बयान में यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगेर ऐंडरसन के हवाले से कहा गया है कि यह एक ऐतिहासिक समझौता हो सकता है, क्योंकि अब प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है। बयान में कहा गया, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि प्लास्टिक के कण उसके शरीर या उसके अजन्मे बच्चों के भीतर पहुंच जाएं। यूएनईपी प्रमुख ने बताया कि औद्योगिक देशों के समूह जी20



में भी इसी भावना को व्यक्त किया गया था। 170 से अधिक देशों और 600 पर्यवेक्षक संगठनों के प्रतिनिधि, दक्षिण कोरिया के बन्दरगाह शहर, बुसान में एक सप्ताह के लिए जुटे हैं, जहां राष्ट्रपति यून सुक येओल ने शून्य प्लास्टिक प्रदूषण की ओर बढ़ने के उपाय पर सहमति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह सभी सदस्य देशों को भावी पीढ़ियों की खातिर एकजुटता दर्शाते होनी होगी और प्लास्टिक प्रदूषण पर सन्धि को अन्तिम रूप देकर एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत करनी होगी। आधिकारिक रूप से इस बैठक को पांचवी अन्तर-सरकारी समिति की वार्ता कहा गया है, ताकि समुद्री पर्यावरण समेत प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय की व्यवस्था की जा सके। इस विषय में बातचीत की शुरुआत 1,000 दिन पहले उरुग्वे में हुई थी और चार सत्रों की वार्ता के बाद अब यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें समझौते की अपेक्षा है। एक बयान में यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर सन्धि को महत्वाकांक्षी, विश्वसनीय और न्यायसंगत बनाना होगा। किसी भी समझौते में प्लास्टिक के जीवन चक्र का ध्यान रखा जाना होगा, सिंगल यूज (एकल-इस्तेमाल) और कम अवधि की प्लास्टिक की समस्या से पहले निपटना होगा। साथ ही, कचरा प्रबन्धन को मजबूती देते हुए वैकल्पिक सामग्री को बढ़ावा दिया जाना होगा। बयान के मुताबिक बैठक के जरिए सभी देशों की टैक्नालॉजी तक पहुंच सुनिश्चित की जानी होगी, जमीन व समुद्री पर्यावरणों को बेहतर बनाना होगा और यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्लास्टिक पर निर्भर समुदायों को साथ लेकर चला जाए।

## माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस के मिश्रण से पर्यावरण को होता है भारी नुकसान- अध्ययन

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए पांचवें दौर की वार्ता जारी है, वार्ता एक दिसंबर तक चलेगी। संधि वार्ता में प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के साथ-साथ इनमें उपयोग होने वाले केमिकलों के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। आज, यानी 25 नवंबर से 175 देशों के प्रतिनिधि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए पांचवें दौर की वार्ता के लिए एकत्र हुए, जो एक दिसंबर तक चलेगी। संधि वार्ता में प्लास्टिक में उपयोग होने वाले केमिकलों के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है।

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि रोजमर्रा की वस्तुओं में उपयोग होने वाले केमिकलों का मिला जुला असर अलग-अलग केमिकलों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने माइक्रोप्लास्टिक्स और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ (पीएफएएस) के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच की और दिखाया कि दोनों जलीय जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण होते हैं जो प्लास्टिक की बोतलों, पैकेजिंग और कपड़ों के रेशों से आते हैं। पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ (पीएफएएस) रसायनों का एक समूह है जिसका उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे नॉन-स्टिक कुकवेयर, जल-प्रतिरोधी कपड़े, अग्निशमन फोम और कई औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। बुसान में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए

पांचवें दौर की वार्ता जारी है, वार्ता एक दिसंबर तक चलेगी। संधि वार्ता में प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के साथ-साथ इनमें उपयोग होने वाले केमिकलों के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। पीएफएएस और माइक्रोप्लास्टिक को फॉरएवर केमिकल के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे आसानी से नहीं टूटते हैं और पर्यावरण में जमा हो जाते हैं, जिससे वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों के लिए इनसे खतरे पैदा हो सकते हैं। पीएफएएस और माइक्रोप्लास्टिक दोनों को जल प्रणालियों के माध्यम से लंबी दूरी तक, आर्कटिक तक ले जाया जा सकता है। वे अक्सर उपभोक्ता उत्पादों से एक साथ निकलते हैं। फिर भी उन दोनों के प्रभाव और जिस तरह से वे पर्यावरण में अन्य प्रदूषणकारी यौगिकों के साथ क्रिया करते हैं, उसे अभी भी ठीक से समझा नहीं गया है। इन प्रदूषकों के मिले जुले प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए, शोधकर्ताओं ने डैफनिया का उपयोग किया, जिसे आमतौर पर पानी के पिस्सू के रूप में जाना जाता है। इन छोटे जीवों का उपयोग अक्सर प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है क्योंकि वे रसायनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे वे पर्यावरण में सुरक्षित रासायनिक सीमा निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छे हैं। बुसान में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए पांचवें दौर की वार्ता जारी है, वार्ता एक दिसंबर तक चलेगी। संधि वार्ता में प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के साथ-साथ इनमें उपयोग होने वाले केमिकलों के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है।